सं.ए-45011/3/2022-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मत्रांलय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को माह जून, 2022 के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

(रविन्दर कुमार) 22/8/22

निदेशक (प्रशा. IV और समन्वय)

दूरभाषः सं. 2309-5244

सेवा में,

1. केंद्रीय मंत्रि परिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, भारत के उपराष्ट्रपति, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के पीपीएस, सचिव (आर्थिक कार्य) के पीपीएस, सचिव (राजस्व) के पीपीएस, सचिव (व्यय) के पीपीएस, सचिव (दीपम) के पीपीएस।
11. श्री वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त)।
14. श्री आशीष वच्छानी, संयुक्त सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग।
15. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार (सी एंड सी / एफएसएलआर / एफएस एंड सीएस) / जेएस (सी एंड सी और ओएमआई)) / जेएस (आईपीपी / जेएस (आईएसडी) / जेएस (आईएनवी) / सभी सलाहकार/ सीएएए

16. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
17. गार्ड फाइल - 2022

सं.ए-45011/3/2022-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मत्रांलय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

विषयः जून, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।

I. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:

बृहद आर्थिक अवलोकन:

जून 2022 के महीने में अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने नीतिगत दर में 75 आधार अंकों की वृद्धि की थी। आरबीआई ने भी रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की थी। जबकि वित्तीय बाजार विश्लेषकों ने पहले से ही दरों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था, इसके अप्रत्याशित रूप से बड़े आकार ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास पर मुद्रास्फीति नियंत्रण को प्राथमिकता दे रहे हैं। फेडरल रिजर्व और आरबीआई ने भी सूचित किया है कि मौद्रिक नीति को और सख्त करना अपरिहार्य और अनिवार्य दोनों है।

हालांकि, भारत में आर्थिक विकास लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हासिल होना प्रतीत होता है जैसा कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में उच्च आवृत्ति संकेतकों की मजबूती में देखा गया है। पीएमआई विनिर्माण और पीएमआई सेवाएं विस्तारक क्षेत्र में बनी हुई हैं। मात्रा और मूल्य दोनों ही दृष्टि से ई-वे बिल की निरंतर वृद्धि आर्थिक गतिविधि के निरंतर स्तरों का एक और प्रतिबिंब है। गूगल गतिशीलता सूचकांक में लगातार वृद्धि के साथ, सेवा क्षेत्र, जो सकल घरेलू उत्पाद के 50 प्रतिशत से अधिक है, कम से कम इस चालू वित्त वर्ष में अब विकास का इंजन बनना प्रतीत होता है।

वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए उनकी तैयारियों का उल्लेख करते हुए, वर्ष के समापन पर उनके मुनाफे में वृद्धि दिखाते हुए, 2021-22 के लिए चौथी तिमाही का डेटा जून 2022 में कारपोरेट और वित्तीय क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय क्षेत्र में 3 जून को समाप्त पखवाड़े में बैंक ऋण में सालाना आधार पर 13.1 प्रतिशत की वृद्धि में अंतर प्रतीत होता है, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है। 2022-23 की पहली तिमाही में निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेश पिछले वर्ष की इसी अवधि में अपने स्तर से ऊपर उठ गया है। दूसरी ओर, कॉरपोरेट क्षेत्र की सुदृढ़ता में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 22-23 की पहली तिमाही में कुल निवेश का 85 प्रतिशत तक बढ़ रही है, जो पिछली 4 तिमाहियों के औसत 63 प्रतिशत से अधिक है। मानसून के आगमन और खरीफ की बुवाई में वृद्धि भी चालू वर्ष में कृषि उत्पादन के दूसरे रिकॉर्ड स्तर के लिए अभी भी अच्छा संकेत है।

वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में विकास की गति धीमी हो सकती है क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति और आरबीआई द्वारा सख्त मौद्रिक उपायों ने मांग को रोकना शुरू कर दिया है। मुद्रास्फीति अंततः कमजोर हो सकती है क्योंकि मांग संयमित है और वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में कई देशों में मौद्रिक सख्ती के साथ और नरमी आई है। हालांकि, भारत जैसे निवल वस्तु आयात पर निर्भर देशों में, चालू खाता घाटे (सीएडी) को बढ़ने से रोकने के लिए कच्चे तेल की कीमतों में पर्याप्त रूप से कमी करना भी आवश्यक है, और इससे भी अधिक क्योंकि मौद्रिक सख्ती के द्वारा विश्वव्यापी मंदी के कारण निर्यात कमजोर हो रहे हैं। सीएडी भी मूल्यह्रास में शामिल हो रहा है और बदले में इससे पोषित हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप सीएडी में गिरावट और रुपये का मूल्यह्रास त्रुटिपूर्ण हो रहा है।

एफपीआई पूंजी की बढ़त से रुपये का मूल्यह्रास भी शुरू हो रहा है क्योंकि फेडरल रिजर्व ने दरें बढ़ाना जारी रखे हुए हैं और रूस-यूक्रेन संकट सतर्क निवेशकों को भारत जैसे उभरते बाजार और

विकास अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी निकालने के लिए मजबूर कर रहा है। हालांकि, देश में डॉलर के अंतर्वाहों को आकर्षित करने के लिए एफडीआई की निरंतर वृद्धि और आरबीआई द्वारा हाल ही में किए गए उपायों से पूंजी की भरपाई हो सकती है।

सरकार के सामने एक अहम चुनौती राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाने की है, अन्यथा यह सीएडी को और अधिक वृद्धि की ओर ले जाएगा, जिससे दोहरे घाटे की समस्या पैदा होगी, जो न केवल देश के वित्त व्यवस्था को अस्थिर बनाता है बल्कि विकास को भी कमजोर करता है। यह चुनौती और भी कठिन होगी क्योंकि एक तरफ बढ़ती मुद्रास्फीति राजस्व व्यय पर अतिरिक्त मांग कर सकती है जबकि पूंजीगत व्यय को कम नहीं किया जा सकता है क्योंकि विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय घाटे को राजस्व पक्ष की ओर से भी चुनौती दी गई है क्योंकि हाल ही में लगाए गए अप्रत्याशित कर और निर्यात शुल्क मई के महीने में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद कर घाटे की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकते हैं।

आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति सितंबर तिमाही के अंत तक और बड़ा आकार ले सकती है। हालांकि, एमपीसी की अपनी आगामी बैठक में आरबीआई द्वारा विकास दर और मुद्रास्फीति के अनुमान चालू वर्ष की शेष राशि के लिए अनुमानित व्यापक आर्थिक स्थिति पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं।

2. महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

i. आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के दौरान एक नई ई-ट्रैकिंग और रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन (नेत्रा) वेबसाइट और भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया।

ii. भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए जीएसआर 783 (ई) के तहत अधिसूचित आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के लोगो की थीम वाले ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 के परिचालन सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला जारी की गई।

iii. "भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के 175 वें वर्ष" पर एक स्मारक सिक्का जारी करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 478 (ई) दिनांक 27 जून, 2022 जारी की गई है।

iv. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के 3 पदेन सदस्यों को राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था।

v. 'इंडो-जर्मन ग्लोबल एकेडमी फॉर एग्रो इकोलॉजी रिसर्च एंड लर्निंग' परियोजना के लिए आर्थिक कार्य विभाग और केएफडब्ल्यू-जर्मन डेवलपमेंट बैंक के बीच 20 मिलियन यूरो का अनुदान समझौता।

vi. इस महीने के दौरान निम्नलिखित ऋण खेप (एलओसी) प्रदान किया गया है:-

(क) यूरिया उर्वरक की खरीद के लिए 55 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का श्रीलंका की सरकार को ऋण खेप (एलओसी)।

(ख) भारत से चावल के निर्यात के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का क्यूबा की सरकार को ऋण खेप।

vii. इस माह के दौरान निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए:-

क) भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए परियोजना वित्त पर ऑनलाइन कार्यक्रम।

ख) आईआईएम कोझीकोड में आयोजित पीपीपी और बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

ग) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) में आयोजित किया गया।